

## मैनुअल संख्या-01 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

# सर्व शिक्षा अभियान

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य तथा जीवनोपयोगी प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में सर्व सुलभ प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में समाहित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया गया। इन योजनाओं में आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला समाख्या, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं जैसे, आंध्र प्रदेश में “सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाएं”, उत्तरांचल में “सभी के लिए शिक्षा परिषद” परियोजना, राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शामिल है। जोमटिन में आयोजित एजुकेशन फार ऑल (सभी के लिए शिक्षा) हेतु आयोजित सम्मेलन के संकल्प के बाद सार्वभौमिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय संकल्प को बल प्राप्त हुआ।

### प्रारम्भिक शिक्षा की आवश्यकता

बुनियादी शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा समानता की उपलब्धता सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा मानव-कल्याण और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है तथा जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार लाती है।

### प्रारम्भिक शिक्षा की संवैधानिक तथा विधिक स्थिति

शिक्षा मानव जीवन की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा देश की विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ एक सबल राष्ट्र के निर्माण हेतु आदर्श नागरिकों का निर्माण भी करती है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के अनुसार—

राज्य का यह प्रयास होगा कि संविधान के लागू होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भिक शिक्षा को मूल अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख अनुशंसायें

संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत नीति निर्देशक सिद्धान्तों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किये जायें, जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

स्कूलों में मौजूदा अपव्यय तथा गतिरोध को दूर करने के लिए समुचित कार्यक्रम तैयार किया जाये और स्कूलों में नामांकित किये गये सभी बच्चे निर्धारित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करें। प्रारम्भिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया गया है :-

- “यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 21 वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन्तोषजनक, गुणवत्ता वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जायेगा।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने जे0पी0 उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य, 1993 के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है :-

“इस देश के नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का स्रोत अनुच्छेद 21 से निकलता है। देश के प्रत्येक बच्चे/नागरिक को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद उसका शिक्षा का अधिकार, राज्य की आर्थिक क्षमता तथा विकास पर निर्भर होगा”।

“14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक नागरिक, जो बच्चों के माता-पिता हैं, का मौलिक कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान बनाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी तदनु रूप संशोधन किया जाना चाहिए।”

प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए जुलाई, 1997 में राज्य सभा में 83 वां संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया गया था।

## शिक्षा मंत्रियों का सेमिनार

वर्ष 1998 में आयोजित शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचे, कि प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एक अनिवार्य कदम के रूप में प्रयास किये जाने चाहिए। इस बात पर सहमति हुई थी कि, प्रारम्भिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए, जिसमें गुणात्मक निवेशों के साथ-साथ बच्चों के सर्वव्यापी नामांकन तथा बच्चे को स्कूल में बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मिशन को केन्द्र और राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग और समुदाय की सहभागिता से चलाया जाना चाहिए।

सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति, सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच पूर्ण सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य को मिशन रूप में प्राप्त करने की कार्यनीति तैयार करेगी।

## प्रारम्भिक शिक्षा की मिशन के रूप में सर्वसुलभता (1999 की समिति की आख्या)

मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा राज्य मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा प्रश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्रियों को इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। समिति ने यह सिफारिश की, कि प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएं तैयार करने पर मुख्य बल देकर, समग्र एवं सकेन्द्रित दृष्टिकोण से मिशन रूप में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इस समिति ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने सम्बन्धी विचार का समर्थन किया और प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रूप में प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की।

### अब तक की स्थिति

अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारे देश ने प्रारम्भिक शिक्षा में संस्थाओं की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के नामांकन की दृष्टि से काफी प्रगति की है। देश के स्कूलों में चार गुना वृद्धि हुई है, अर्थात् वर्ष 1950-51 में 2,31,000 के मुकाबले वर्ष 1998-99 में स्कूलों की संख्या 9,30,000 हो गई। जबकि प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में 6 गुणा वृद्धि हुई है अर्थात् यह संख्या 1.92 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ तक पहुँच गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इस अवधि के दौरान नामांकन में 13 गुना वृद्धि हुई थी, जबकि लड़कियों के नामांकन में 32 गुना की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन औसतन 100 प्रतिशत बढ़ा है। स्कूलों तक पहुँच अब कोई बड़ी बात नहीं रही। प्राथमिक स्तर पर देश के ग्रामीण जनसंख्या वाले 94 प्रतिशत स्थानों में एक किलोमीटर के भीतर स्कूल की सुविधा है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह सुविधा तीन किलोमीटर के भीतर 84 प्रतिशत है।

भारत में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति उत्साहजनक है शिक्षा के लिए समुदाय की काफी मांग है। विशेष रूप से महिलाओं एवं लड़कियों की साक्षरता तथा स्कूल उपस्थिति की दर में वृद्धि से इस स्थिति का आभास होता है। वर्ष 1998-99 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि 6-14 आयु वर्ग के लगभग 79 प्रतिशत लड़के तथा लड़कियाँ स्कूल जा रहे हैं जबकि वर्ष 1992-93 में 68 प्रतिशत लड़के व लड़कियाँ स्कूल जाते थे। शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े भी उत्साहवर्धक हैं तथा राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण 1997-98 के 53 वें दौर तक इस प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्कूल उपस्थिति के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष के अन्तर का अधिक होना, चिन्ताजनक विषय है। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की शिक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके लक्ष्य को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्यों में कुछ प्रयास किए गए हैं, जिनमें सामुदायिक सहभागिता से शिक्षक रिक्रियाँ बड़े पैमाने पर भरना तथा जिन बस्तियों में स्कूल नहीं हैं, उनमें स्कूल खोलना शामिल है। पंचायती राज संस्थानों की संरचना में स्कूलों के प्रभावी प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी हमारे संवैधानिक संकल्प को पूरा करने में काफी हद तक सहायक हुई हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। लेकिन 6-14 आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में 5.9 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का वर्ष 1995-96 का 53 वां दौर) इनमें 3.5 करोड़ लड़कियाँ तथा 2.4 करोड़ लड़के हैं। ये समस्याएँ पढ़ाई बीच में छोड़ने की अधिक दर, अधिगम उपलब्धि

का निम्न स्तर और लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य अपवंचित वर्गों की कम सहभागिता से सम्बन्धित है। अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तियां/टोलें हैं, जहाँ एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूली सुविधायें नहीं हैं। संक्षेप में देश को अभी भी प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यु0ई0ई0) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसका तात्पर्य है सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाएं प्रदान करके शत-प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाये रखना। इसी अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

## सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध, समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने सम्बन्धी अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सार्थक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान, जिससे देश के प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को, मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

## सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल एवं बैक-टू-स्कूल शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें।
- सभी बच्चे वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
- सन्तोषजनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया हो, पर बल देना।
- बालक/बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना।

## कार्यक्रम की विशेषताएं

1. असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
2. बाल श्रमिकों, अल्प संख्यक/अनुसूचित जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए पृथक प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था।
3. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था।

4. ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय की प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन तथा निर्माण कार्यों में सक्रिय भूमिका।
5. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
6. प्राथमिक शिक्षा के भवनों की नियमित मरम्मत एवं रखरखाव।
7. सभी प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालयों की व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण।
8. प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को विद्यालय विकास हेतु ₹0 2000/- का अनुदान।
9. प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक को प्रति वर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी हेतु ₹0 500/- का अनुदान।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों तथा समस्त बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था।
11. अक्षम एवं विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा।
12. दूर शिक्षा कार्यक्रम का विकास।
13. स्वयंसेवी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग।
14. नवाचारी कार्यक्रमों को प्रमुखता।
15. पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों का विकास व अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण।
16. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण।
17. विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
18. नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त अध्यापकों के पदों का सृजन।
19. माईक्रोप्लानिंग (सूक्ष्म नियोजन) तथा स्कूल मैपिंग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का नियोजन।
20. कम्प्यूटर आधारित शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली का विकास।
21. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण।

## सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीतियाँ

### संस्थागत सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रूप में राज्यों में संस्थागत सुधार किए जाएंगे। राज्यों को अपनी मौजूदा शैक्षिक पद्धति का वस्तुपरक मूल्यांकन करना होगा, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामले, विकेन्द्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की

तैनाती को तर्क सम्मत बनाना, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सुविधाहीन वर्गों के लिए शिक्षा, निजी स्कूलों तथा ई0सी0सी0ई0 सम्बन्धी मामले शामिल होंगे।

## विशेष समूहों पर ध्यान

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों, अपवंचित वर्गों के बच्चों और विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

## परियोजना पूर्व चरण

सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में सुनियोजित रूप से परियोजना पूर्व चरण प्रारम्भ करेगा। मानीटरिंग पद्धति में सुधार कर क्षमता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाएगा इनमें बस्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए समुदाय आधारित सूक्ष्म-नियोजन, स्कूल मैपिंग का प्रावधान, विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण को शामिल करना, उपचारात्मक अध्ययन, सामुदायिक गतिशीलता के लिए क्रियाकलाप, सूचना पद्धति तैयार करने के लिए सहायता, कार्यालय उपस्कर आदि का प्रावधान शामिल है।

## गुणवत्ता पर बल देना

सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या में सुधार करके तथा बाल केन्द्रित कार्यकलापों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर, प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा को उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है।

## शिक्षकों की भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है ब्लॉक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र की स्थापना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पाठ्यचर्या से सम्बन्धित सामग्री के विकास में सहयोग के जरिए, शिक्षक विकास के अवसर शिक्षा सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर ध्यान देकर और शिक्षकों के एक्सपोजर दौरे, शिक्षकों के बीच मानव संसाधन को विकसित करने के उद्देश्य से कार्ययोजनाओं का निर्माण किया जाता है।

## जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएँ

सर्व शिक्षा अभियान के कार्य ढाँचे के अनुसार, प्रत्येक जिला एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, जो समग्र दृष्टिकोण से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों को दर्शाएगा।

## प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता

प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के अनुसार, अगले 10 वर्षों के लिए, केन्द्र और राज्य स्तरीय विभागों के बजट से लगभग ₹0 60,000 करोड़ के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का एक सशक्त माध्यम है। अतः अतिरिक्त संसाधनों एवं

विद्यालयों की भौतिक स्थिति में सुधार लाने हेतु अतिरिक्त संसाधनों एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु बजट एवं संसाधनों की आवश्यकता है।

## सतत् वित्तपोषण

सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम पर वित्तपोषण सतत् जारी रखा जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता पर दीर्घकालीन परिपेक्ष्य की अपेक्षा है।

## सामुदायिक स्वामित्व

इस कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सामुदायिक स्वामित्व की अपेक्षा है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।

## संस्थागत क्षमता निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद/सीमेट (एस0आई0ई0एम0ए0टी0) जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है। गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग वाली प्रणाली की आवश्यकता है।

## शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा का सुधार

इसमें संस्थागत विकास, नई पहल को शामिल करके और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियाँ अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्यधारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

## पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक अनुश्रवण

इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित पद्धति अपनायी जायेगी। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना पद्धति, सूक्ष्म आयोजना और सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कूल स्तरीय आँकड़ों का सम्बन्ध स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल एक नोटिस बोर्ड रखेगा, जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त किए गए सारे अनुदान और अन्य ब्योरे दर्शाए जाएँगे।

## योजना एकक के रूप में बस्ती

सर्व शिक्षा अभियान, आयोजना की इकाई के रूप में बस्ती के साथ योजना बनाते हुए, समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है। बस्ती योजनाएं जनपदों की योजनाओं को तैयार करने का आधार होंगी।

## समुदाय के प्रति जबाबदेही

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सहयोग तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

## लक्षित समूहों की शिक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी तथा समस्त बालिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का लक्षित समूह है।

## सर्व शिक्षा अभियान के पहलू

1. यह प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यापक सकेन्द्रित ढाँचा प्रदान करता है।
2. यह प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए बजट प्रावधान करने वाला कार्यक्रम है। हालांकि राज्यों और केन्द्रीय योजनाओं से प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र के सभी निवेश, सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे के भाग के रूप में दर्शाए जाएंगे, ये अगले कुछ वर्षों के भीतर सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिए जाएंगे। कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए ये अतिरिक्त बजट प्रावधान करती हैं।

## वित्तीय प्रतिमान

- सर्व शिक्षा अभियान के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी नौवीं योजना अवधि के दौरान 85:15, दसवीं योजना अवधि में 75:25 तथा उसके बाद यह 50:50 की होगी। लागत को वहन करने की वचनबद्धता राज्य सरकारों से लिखित रूप में ली जाएगी।
- भारत सरकार केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ जारी करेगी तथा केन्द्र सरकार की पिछली किश्तों (प्रथम किश्त के अलावा) तथा राज्य सरकार के हिस्से को राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को अंतरित करने के बाद ही अगली किश्त जारी की जाएगी।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त किए गए शिक्षक के वेतन में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी नौवीं योजना अवधि के दौरान 85:15 के अनुपात में, दसवीं योजना अवधि के दौरान 75:25 के अनुपात में तथा इसके बाद 50:50 के अनुपात में होगी।
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में किए गए सभी विधिक समझौते लागू रहेंगे, जब तक कि विदेशी निधियाँ प्रदान करने वाली एजेन्सी से विचार विमर्श करके इसमें कोई विशिष्ट संशोधन करने पर सहमति नहीं हो जाती।



- विभाग की मौजूदा योजनाएँ (राष्ट्रीय बाल भवन और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के अलावा नौवीं योजना के बाद मिला दी जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम योजना (मध्याह्न भोजन योजना) एवं विशिष्ट योजना के रूप में कायम रहेंगी। जिसमें खाद्यान्न एवं यातायात की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी तथा भोजन पकाने की लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायेगी।
- स्कूलों के स्तर में वृद्धि, रखरखाव, मरम्मत, अध्ययन-अध्यापन उपस्करों तथा स्थानीय प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी निधियां वी0ई0सी0/स्कूल प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कर दी जायेगी।
- अन्य प्रोत्साहन योजनाओं, जैसे छात्रवृत्ति तथा गणवेश प्रदान करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत निधियां जारी की जाती रहेंगी। इन्हें सर्व शिक्षा अभियान से निधियां नहीं दी जाएंगी।

## सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य कार्यनीतियाँ

### उपागम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयोगों (कार्यों) और आवश्यकताओं के अनुसार प्रदेश, जनपद स्तरों पर सहभागी प्रक्रिया सम्मिलित कर, योजना निर्माण में विकेन्द्रीकृत उपागम अंगीकार किया गया। अपवंचित वर्गों विशेषकर महिला सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों, गाँव, न्याय पंचायत (10-12 गांवों का संकुल) ब्लॉक तथा जनपद स्तरों के अभिकर्मियों की खुली बैठकों में विचार-विमर्श एवं सघन अन्तः क्रिया से उभरे मुद्दों, समस्याओं, रणनीतियों और निवेशों पर आधारित परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गयी। इस सहभागी नियोजन की प्रक्रिया में न केवल शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों को सम्मिलित किया गया है अपितु जनपद स्तर के अन्य विभागों से सम्बन्धित विकास अभिकर्मियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सक्रिय भागीदार बनाया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सम्भव हुआ कि योजनाओं के स्वामित्व की सुदृढ़ भावना का उनमें विकास हुआ है, जो जनपद और उप जनपद स्तरीय अभिकर्मियों द्वारा वास्वविक और क्रियान्वयन योग्य है।

### समग्र

सर्व शिक्षा अभियान नियोजन और प्रबन्ध को समग्र उपागम प्रदान करता है, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्य को इसकी सम्पूर्णता का बोध कराता है। यह अभियान सभी कारकों के समेकित दृष्टिकोण को ग्रहण करता है, जो शैक्षिक प्रणाली को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वहन करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान समग्र नियोजन एवं प्रबन्ध पर बल देता है एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को इसकी सम्पूर्णता में सम्प्राप्ति के लिए आवश्यक समस्या मापदण्डों के समेकन (एकीकरण) पर विचार करता है।

### प्रासंगिक

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिए एक समेकित और व्यापक परियोजना है। इसके अन्तर्गत जनपद की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का निर्माण/विकास किया गया है। इसमें वर्ग भेद दूर करने के लक्ष्य और विकेन्द्रित नियोजन एवं प्रबन्ध सहित स्थानीय क्षेत्र नियोजन सम्मिलित है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की अधिप्राप्ति के लिए विविध प्रसंगों

विशेषकर बालिकाओं और अपवंचित वर्गों की समस्याओं पर विचार करते हुए, नियोजन स्थानीय इकाइयों की आवश्यकताओं की विषमता पर आधारित है।

## सहभागी

सर्व शिक्षा अभियान की मान्यता है कि कार्यक्रम की सफलता और प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामुदायिक सहभागिता मुख्य घटक है। इसीलिए कार्यक्रम नियोजन और प्रबन्ध में सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं, शिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और पूरे समुदाय की घनिष्ठ अन्तः क्रिया पर ध्यान देता है ताकि प्रदेश के कतिपय शैक्षिक दृष्टि से सबसे पिछड़े जनपदों में प्राथमिक शिक्षा का प्राविधान करने में उनकी अपनी आवश्यकतायें और अपेक्षायें परिलक्षित हो सकें। कार्यक्रम समुदाय की गतिशीलता की वर्तमान स्थिति से वहां तक जाना चाहता है, जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा के लिए समुदाय का स्वामित्व स्थापित हो सके।

## कार्यक्रम के घटक

### 1. पहुंच (Access) विस्तार

- \* 1.5 किमी<sup>0</sup> की परिधि में 300 आबादी वाली असेवित बस्तियों के मैदानी क्षेत्रों तथा 01 किमी<sup>0</sup> की परिधि में 250 आबादी वाली असेवित बस्तियों के पर्वतीय क्षेत्रों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
- \* कामगार बच्चों, असहाय बच्चों, अल्प संख्यक समुदाय की बालिकाओं, अपवंचित बालिकाओं, अपवंचित वर्गों और विकीर्ण बस्तियों के लिए विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक प्रतिरूप उपलब्ध कराना।

### 2 धारण प्रोत्साहन

- \* जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबन्धन के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना।
- \* प्राथमिक विद्यालय भवनों का नियमित पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
- \* समस्त प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करना।
- \* 3-6 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय जाने की तैयारी के लिए प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना और बड़ी बालिकाओं को सगे भाई बहिनों के देख-रेख के दायित्व से मुक्त करना।
- \* हल्के व संयत/अधिगम एवम् शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील कर अधिकारों से शक्ति सम्पन्न बनाना।
- \* महिला समूहों, युवामंगल दलों, माता शिक्षक संघों तथा अभिभावक शिक्षक संघों आदि जैसे मूल स्तरीय ढांचों की स्थापना तथा सुदृढीकरण करना।

- \* महिलाओं की गतिशीलता एवं शक्ति सम्पन्नता के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम का विस्तार करना।

### 3 गुणवत्ता संवर्द्धन

- \* क्रिया आधारित अधिगम एवं बाल केन्द्रित अधिगम को प्रोत्साहित करने और बच्चों तथा शिक्षकों के मध्य द्विमार्गीय अन्तः क्रिया की सुविधा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों और पाठ्यक्रम की समीक्षा तथा संशोधन।
- \* अभिप्रेरण और विलक्षणता (विजिनिंग) अभ्यासों को सम्मिलित कर शिक्षकों के लिए गुणवत्ता संवर्द्धन रणनीतियाँ और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- \* शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण मंजूषा (पैकेज) जैसे संदर्शिकाओं, पैकेजों तथा अल्प व्यय शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्धन।
- \* न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों की नियमित अकादमिक संसाधन सहायता सुनिश्चित करना और उनके विद्यालयी कार्य निष्पादन का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।
- \* बहुश्रेणी शिक्षण (बहु कक्षा शिक्षण) के लिए रणनीतियों का विकास।
- \* शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय तकनीकों का विकास।
- \* सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण और उपयुक्त दूर शिक्षा के माध्यम से सम्प्रेषण क्षति को कम करना।

### 4. क्षमता विकास

- \* राज्य परियोजना कार्यालय का सुदृढीकरण।
  - \* विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री का विकास, मूल्यांकन प्रणाली और आधार भूत आंकलन, अध्ययन सम्पादन आदि में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की संस्थागत क्षमता का सुदृढीकरण।
  - \* परियोजना के शैक्षिक नियोजन प्रबन्धन और शोध में संलग्न अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा परियोजना क्रियाकलापों के शैक्षिक सांख्यिकी के मूल्यांकन, विश्लेषण और अभिलेखीकरण में संस्थानिक क्षमता का अभिवर्द्धन करना।
- क – समय से पाठ्यपुस्तक के वितरण की व्यवस्था का सुदृढीकरण।
- ख – पाठ्य पुस्तकों के विकास की समुन्नत प्रणाली के लिए डी0टी0पी0 की सुविधा प्रदान कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा उत्तरांचल विद्यालय एवं परीक्षा परिषद का सुदृढीकरण।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- \* सर्व शिक्षा अभियान के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रण सामग्रियों के उत्पादन, विकास तथा अभिकल्पन के क्षेत्र में तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग के लिए उन्नत उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से सुदृढ़ करना और संस्थाओं को सहायता देना।
- \* कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त स्टाफ की व्यवस्था, उपकरण, पुस्तकों और वाहन आदि से जिला परियोजना कार्यालयों की स्थापना और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।
- \* शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक क्रियाकलापों में सहायता के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु परियोजना जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड (ब्लॉक) में ब्लॉक संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- \* शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विकेन्द्रित सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- \* सूक्ष्म नियोजन (विद्यालय मानचित्रण और घर-घर सर्वेक्षण) सामुदायिक सहायता में गतिशीलता, विद्यालय सुधार और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण में सम्मिलित करने हेतु ग्राम शिक्षा एवं विद्यालय प्रबन्ध समितियों को क्रियाशील बनाना।
- \* नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकों के यथा समय वितरण पर बल।

### सर्व शिक्षा अभियान के घटक

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रारम्भिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार, अध्ययन-अध्यापन सामग्रियों का प्रावधान, शैक्षिक सहायता के लिए ब्लॉक और संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना, कक्षाओं और स्कूल भवनों का निर्माण शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना और विकलांगों की समेकित शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा शामिल है।

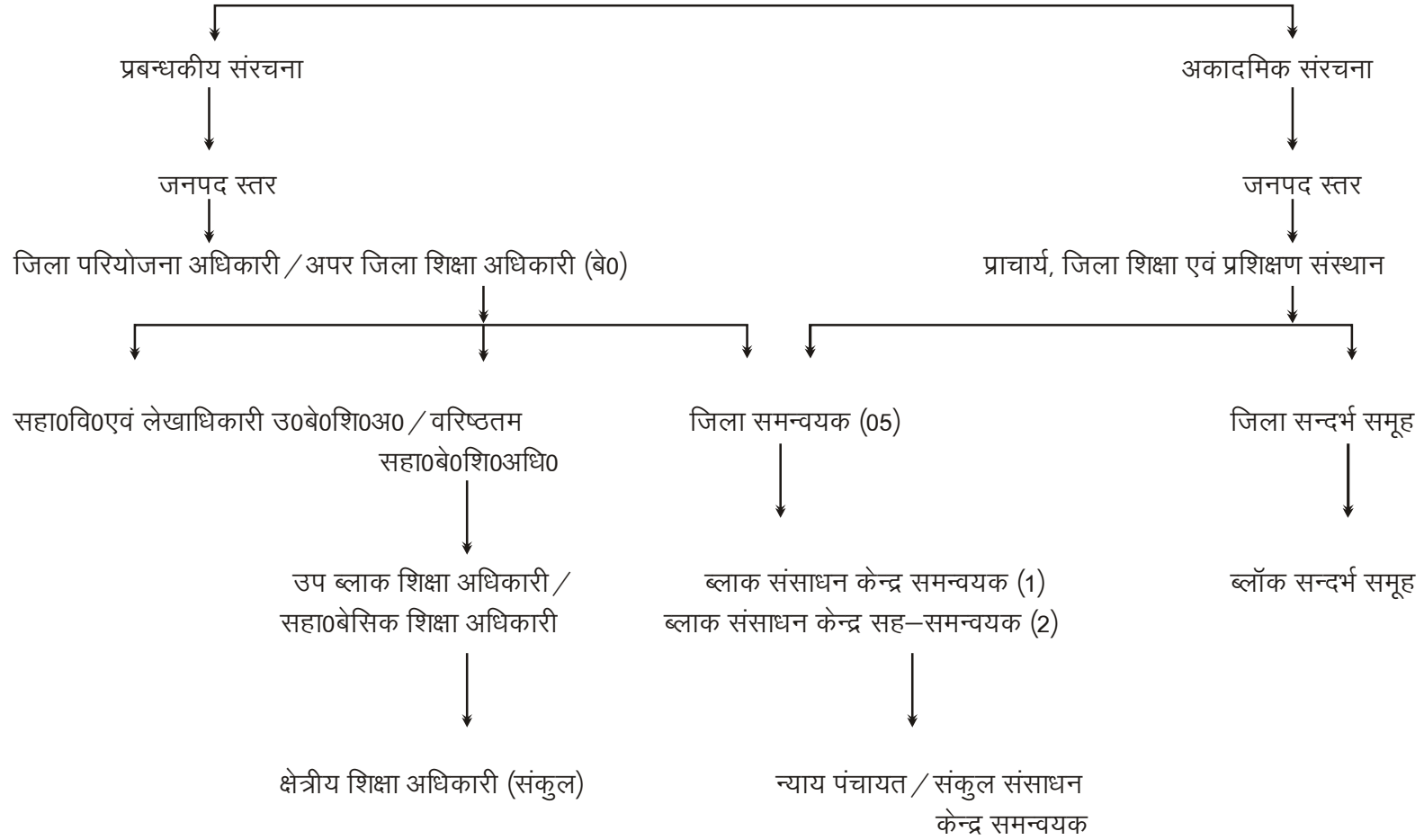
### मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

शासकीय स्तर	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली.नं० / ई-मेल
1) मुख्यालय	राज्य परियोजना निदेशक	उत्तरांचल सभी के लिए भिक्षा परिषद, मयूर विहार, सहस्रधारा रोड़, देहरादून	2781941 2781942 2781943 uadpep@vsnl.net
हरिद्वार	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) हरिद्वार	जिला परियोजना कार्यालय (SSA) कनखल, हरिद्वार	01334-246113
चम्पावत	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) चम्पावत	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), गोरल चौड़ रोड़, चम्पावत	05965-230614

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), बद्री केदार टूरिस्ट लॉज, रुद्रप्रयाग	1364-233943
बागेश्वर	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) बागेश्वर	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), तहसील रोड़, बागेश्वर	05963-220653
नैनीताल	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), मल्लीताल, नैनीताल	05942-232520
पिथौरागढ़	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) नैनीताल	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), पिथौरागढ़	05964-226881
अल्मोड़ा	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) अल्मोड़ा	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), जाखन देवी, अल्मोड़ा	05962-2237132
ऊधमसिंह नगर	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) रुद्रपुर	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), रुद्रपुर	05944-441522
पौड़ी	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) पौड़ी	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), शिक्षा संकुल, पौड़ी	01368-223872
टिहरी	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) टिहरी	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), टिहरी	01375-233436
चमोली	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) चमोली	जिला परियोजना कार्यालय (शिक्षा संकुल) (SSA), गोपेश्वर, चमोली	01372-253363
उत्तरकाशी	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) उत्तरकाशी	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), उत्तरकाशी	01374-226267
देहरादून	जिला परियोजना अधिकारी (SSA) देहरादून	जिला परियोजना कार्यालय (SSA), प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून	0135-2675227

शिक्षण संरचना का विवरण  
 शिक्षण संरचना का विवरण  
 शिक्षण संरचना का विवरण





संख्या 552

पत्रावली सं०-14984d

दिनांक 22-05-06



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या 89/2006 - 2007

फाइल संख्या 14984d

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद एडीशनल डायरेक्टर, उत्तरांचल, 2 सुभाष रोड, देहरादून को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 819/2000-2001 दिनांक 17/02/2001 को दिनांक 17/02/2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

700.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 18/05/2006

सोसाइटी-रजिस्ट्रार  
उत्तरांचल।



## Uttaranchal Sabhee Ke Liye Shiksha Parishad

### Memorandum of Association

1. **Name of the Society:** The name of Society shall be "Uttaranchal Sabhee Ke Liye Shiksha Parishad"(hereinafter referred to as "The Parishad").
2. **Area of operation:** The area of operation of the society shall be the state of Uttaranchal.
3. **Location:** The registered office of the Parishad shall be located in Uttaranchal at Dehradun. Address: Camp office, Additional Director Uttarakhand 2 Subhash Road, Dehradun.
4. **Objects:** The Parishad shall act as an autonomous and independent body for implementation of any type of educational projects such as the Government of India sponsored District Primary Education Programme – III running in Uttaranchal & the Sarva Shiksha Abhiyaan. The Parishad shall also function as a societal mission for bringing about a fundamental change in the basic, secondary, higher, integrated, technical, vocational, computer, non- formal/alternative and innovative education & literacy programmes and through it in the overall socio-cultural situation. The following specific objects shall be pursued by the Parishad.
  - [a] Universalisation of Elementary Education, viewed as a composite programme of [i] access to primary education for all children upto 11 years of age; [ii] universal participation till they complete the elementary stage through formal or alternative & innovative education system; [iii] universal achievement atleast of the minimum levels of learning; and [iv] to emphasize formal/non-formal, secondary, higher, integrated, technical, vocational, computer & literacy programmes.
  - [b] Provision for continuing education and skill development programmes for youth.
  - [c] Making suggestions for greater gender equality in education and female empowerment.
  - [d] Making necessary intervention to provide equal educational opportunity to boys & girls belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and the Weaker Sections of Society.
  - [e] Provide necessary support in the form of aid & appliances for the physically and mentally challenged children in the 6-14 age group.
  - [f] Laying special emphasis on educational activities such as culture, tourism, communication/information, computer technology, science and environment and inculcation of a sense of social justice.
5. **Functions:** To achieve the above objects, the functions to be undertaken directly by the

Parishad office staff, or sponsored/ supported by it through other institutions, agencies or individuals, shall be as follows:

- [A] To undertake all activities that may be necessary for the implementation of the Educational Projects and in particular for the achievement of the objects referred to in Article 4 above.
- [B] To create duly empowered administrative mechanisms, through such participation, as may be deemed necessary of various departments such as Women & Child Development, Health, Social-Welfare, Tribal- Welfare, Development, Jal Nigam etc. and autonomous bodies and other agencies of the Central Government and State Government.
- [C] To establish for the implementation of the Educational Projects District Task Force:, and other appropriate mechanisms at the District, Block, Nyaya Panchayat and village levels, and to delegate necessary powers to enable them to discharge their responsibilities.
- [D] To secure active involvement and participation of educational institutions, voluntary agencies, teachers and individuals committed to educational improvement and to provide financial assistance to them.
- [E] To bring about effective decentralization in formal & non-formal education by involvement of the people through a process of training and awareness programmes and creation of appropriate structures, formal or otherwise.
- [F] To secure constructive and participatory involvement of teachers through training for the achievement of the Parishad's objectives.
- [G] To take up experimental and innovative programmes in basic, secondary, integrated, non-formal, alternative & innovative education system.
- [H] Maintaining proper records & strengthening Educational Management & Information System for a responsible and flexible manpower planning to maintain enrolment & adequate teacher pupil ratio.
- [I] To undertake and promote research and studies relating to education and its management.
- [J] To ensure technical resource support by harnessing the existing institutions and capacity building such as DIET's.
- [K] To advise the State Government & education department in implementation of different

educational programme.

- [L] To organize conferences, symposia, workshops etc. on matters related to the educational programme.
- [M] To undertake preparation and production of educational materials and to disseminate the same.
- [M] To establish co-ordination, co-operation & networking with special training institutions/organization, universities, national & inter-state institutes working in the area of primary, secondary & higher education.
- [O] To implement systematic arrangement for mobile, community, school/ college libraries.
- [P] To create academic, technical, administrative, managerial and other posts in the Parishad and to make payments for the same in accordance with the rules and regulations of the Parishad.
- [Q] To make rules and regulations for the conduct of the affairs of the Parishad and add or amend, vary or rescind them from time to time.
- [R] To accept or to provide any grant of money, loan securities or property of any kind and to undertake and accept the management of any endowment trust, fund or donation not inconsistent with the objects of the Parishad.
- [S] To incur expenditure after drawing up a budget with due regard for economy and propriety.
- [T] To prepare annual report and accounts of the Parishad.
- [U] To purchase, hire, take on lease, exchange or otherwise acquire property, movable or immovable and construct, alter and maintain any building or buildings as may be necessary for carrying out the objects of the Parishad.
- [V] To take all such actions and measures as may appear necessary or incidental for the achievement of the objects of the Parishad.

6. The names, addresses, occupation and designations of the members of the Executive Committee of the Parishad to whom by the rule and regulations of the Parishad, the management of its affairs is entrusted as required under section 2 of the Societies Registration Act (Act no. 21 of 1860), 1860 are as follows:

*सूचना का अधिकार अधिनियम 2005*

i	Chief Secretary, Government of Uttaranchal, Dehradun	Chairman Ex-officio
ii	Secretary, Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Vice-chairman Ex-officio
iii	Secretary or his nominee, Department of Finance & Planning, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
iv	Secretary Department of rural Development & Panchayati Raj, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
v	Addl. Secretary, Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
vi	Director of Education Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
vii	Addl. Director of Education, Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
viii	Joint Director Technical Education	Member, Ex-officio
ix	State Project Director of the Parishad	Member-Secretary Ex-officio

A copy of the Rules of the Parishad, certified to be a correct copy by the three members of the executive committee of the Parishad if filed along with this Memorandum of Association.

7. We, the several persons, whose names and addresses are given below, having associated ourselves for the purpose described in this Memorandum of Association do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands hereunto and form ourselves into a society under the Societies Registration Act (Act no. 21 of 1860), 1860 this **14 February 2001** at Dehradun.

S. No.	Name	Address	Designation	Profession	Signature
1	Ajay Vikram Singh	Chief Secretary, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member	Govt. Service	Sd/-
2	Dr. R.S. Tolia	Principal Sect. & Commissioner Forest & Rural development, Govt. of Uttaranchal	Member	Govt. Service	Sd/-
3	N. Ravi Shankar	Secretary Department of Education Govt of Uttaranchal, Dehradun\SPD Uttaranchal,	Member/ Secretary	Govt. Service	Sd/-

4	Indu Kumar Pande	Secretary Department of Finance & Planning, Govt. of Uttaranchal, Dehradun	Member	Govt. Service	Sd/-
5	Dr. Dilbag Singh	Addl. Secretary Department of Education Government of Uttaranchal, Dehradun	Member	Govt. Service	Sd/-
6	S. C. Sharma	Joint Director Technical Education, Uttaranchal, Dehradun	Member	Govt. Service	Sd/-
7	Nand Nandan Pandey	Director of Education, Uttaranchal, Dehradun	Member	Govt. Service	Sd/-
8	M.C. Pant		Member	Govt. Service	Sd/-

## RULES OF THE UTTARANCHAL SABHEE KE LIYE SHIKSHA PARISHAD

1. **Name of the society:** The name of the society shall be "Uttaranchal Sabhee Ke Liye Shiksha Parishad".
2. **Address of the Society:** Dehradun, Uttaranchal, 2 Subhash Road, Dehradun.
3. **Short Title:** These rules shall be called "Rules of the Uttaranchal Sabhee Ke Liye Shiksha Parishad".
4. **Scope and Application:**
  - (1) These Rules shall extend to all the units and activities of the Parishad in the State of Uttaranchal.
  - (2) These Rules shall come into force from the date on which the Parishad is registered under the Societies Registration Act, 1860 as applicable to the State of Uttaranchal.
5. **Definitions:** In these Rules, unless the context otherwise requires.
  - (i) "Education" shall mean - board
  - (a) Whether through the formal schools/colleges/institutions or non formal alternative & innovative system, inclusive of Early Childhood Care and Education.
  - (b) Educational and other programmes aimed at women's equality and empowerment.
  - (c) Continuing education, including skill development.

- (ii) "Central Government" shall mean Government of India (Ministry of Human Resource Development, Department of Education).
- (iii) The "Chairman" shall mean the Chairman of the Executive Committee of the Parishad.
- (iv) "District Education Project Committee" shall mean the district level executive committee as envisaged by the Executive Committee.
- (v) The "Executive Committee" shall mean the body which is constituted under Rule 22 as the Executive Committee of the Parishad.
- (vi) "Government" shall mean Government of Uttaranchal.
- (vii) Alternative & innovative education & Non-Formal Education shall mean part-time education provided to those who could not join any formal system of education.
- (viii) "Officers and Staff" shall mean all whole-time and part-time employees of the Parishad appointed by the Executive Committee or any authority or officer delegated with the power to do so, and would include Consultants, Fellows and Research Staff, but would not include State Project Director.
- (ix) The "Parishad" or "the Society" shall mean the Uttaranchal Sabhee Ke Liye Shiksha Parishad.
- (x) "Project" means any type of educational activity based programme.
- (xi) The "President" shall mean the President of the Parishad.
- (xii) The "State Project Director" shall mean the project director of the Parishad appointed by the Government of Uttarakhand under Rule.
- (xiii) "Department of Education" shall mean Department of Education, Government of Uttaranchal.
- (xiv) "Technical Resource" shall mean (i) development of curriculum and teaching/learning materials, (ii) instructional methods; (iii) training of teachers; (iv) development of educational technology; (v) vocational guidance & training (vi) media and communication; and learner evaluation.
- (xv) The "Vice-President" shall mean the Vice-President of the Parishad.
- (xvi) "Voluntary Agencies" shall mean non-government organizations who have been assigned responsibility for execution of any activity under the Project by an authority empowered to do so, and would include registered societies, public trusts and non-profit making companies.
- (a) Words imparting the singular number also include the plural number and vice-versa.
- (b) Words imparting the masculine gender also include feminine gender.

## THE PARISHAD

The Parishad shall consist of the following members; provided that in case the state is under the President rule, the Governor and the Advisors to the governor would discharge functions of President, Vice-President and members from serial (i) to (v) of the Parishad.

(i)	Chief Minister, Uttaranchal	President Ex-officio
(ii)	Minister of Education, Uttaranchal	Vice- president Ex-officio
(iii)	Minister of Planning and Finance, Uttaranchal	Member
(iv)	Minister of Rural Development & Panchayati Raj, Uttaranchal	Member
(v)	Minister of Social Welfare, Child and Women Development, Uttaranchal	Member
(vi)	Chief Secretary, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(vii)	Agriculture Production Commissioner Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(viii)	Secretary, Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(ix)	Secretary, Department of Planning and Finance, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(x)	Secretary, Department of Child Development & Women, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(xi)	Secretary, Department of Rural Development and Panchayati Raj, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(xii)	Add. Secretary, Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member Ex-officio
(xiii)	Director of Education, Uttaranchal	Member Ex-officio
(xiv)	Add. Director of Education, Uttaranchal	Member Ex-officio
(xv)	Director/Nominee of Deptt. of Women and Child Development Uttaranchal	Member Ex-officio
(xvi)	Three persons drawn from non-government agencies engaged in education activities in the State of which at least one would be a woman and one of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes to be nominated by the State Government.	Member

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(xvii)	Upto five heads of relevant State level institutions, engaged in academic and technical resource development to be nominated by the State Government.	Member
(xviii)	Following persons to be nominated by the State Government.	Member
(a)	Three teachers, including at least one woman and one of scheduled castes/Scheduled Tribes to represent basic teachers.	
(b)	Three persons, including at least one woman and one of Scheduled castes/Scheduled tribes to represent instructors and other functionaries engaged in Alternative & innovative Education/non-formal education/ continuing education/literacy campaign etc.	
(c)	Three teachers known for their commitment to Secondary education system, of which atleast one would be a woman and one of Scheduled Caste/Scheduled Tribe.	
(xix)	Other Ex-officio representative of the Government of Uttaranchal	Member
(a)	All heads of District Committee in the selected districts of the project.	
(b)	Three heads of department of State Council of Education Research and Training whose function relate to basic/secondary education.	
(c)	All Executive heads of the District Task Force.	
(xx)	Representatives of Central Government.	Member
(a)	Three representative/Nominees of the central Government to be nominated by the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Government of India.	
(b)	Director, National Council of Educational research and training, New Delhi.	
(c)	Director, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.	
(d)	Two Educationists known for their experience and interest in education, one each to be nominated by State Government and Central Government.	



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(xxi)	Three persons each from voluntary agencies amongst those who have distinguished themselves in the area education for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and physically handicapped, one person in each category to be nominated by the Central Government and State Government	Member
(xxii)	Two women who have distinguished themselves in the area of formal education, alternative and innovative education. Non-formal education and women's development, one person in each category to be nominated by the Central Government and State Government.	Member
(xxiii)	State Project Director	Member Secretary Ex-officio

7. The term of non-official members nominated by the Central Government and State government shall be 2 years or the unexpired period thereof in respect of a member nominated to fill in a vacancy.
8. Members of the Parishad shall cease to be such members, if
  - (a) They resign or are of unsound mind or are insolvent or are convicted of a criminal offence involving moral turpitude; or
  - (b) They do not attend three consecutive meetings of the Parishad without proper leave of the President.
9. Where a member of the Parishad becomes a member by reason of the office of appointment he holds, his membership of the Parishad shall terminate when he ceases to hold that office of appointment.
10. A resignation of the membership of the Parishad shall be tendered to the State Project Director and shall not take effect unless it has been accepted by the Parishad.
11. Vacancies: Any vacancy in the non-official membership of the Parishad shall be filled by the nomination of the authorities entitled to make nominations, and the person nominated in the vacancy shall hold office only for the remaining period of term of the membership.
12. The Parishad shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by the reason of his/her office, is not a member of the Parishad for the time being and notwithstanding any other vacancy in the body, whether by non-nomination or otherwise, and no act of the Parishad shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above event or any defect in the nomination of any of the members of the Parishad.

## **POWER AND FUNCTIONS OF THE PARISHAD**

13. The Parishad shall have following powers and functions:
- (i) To review the implementation of the educational Projects and to give overall policy guidance and direction for efficient functioning of the Parishad.
  - (ii) To consider the balance sheet and audited accounts for the previous year.
  - (iii) To consider the annual report prepared by the Executive Committee.
  - (iv) To add and to amend the Rules of the Parishad, with the approval of the State Government and the Central Government.
  - (v) To perform such other functions as are entrusted to it under these rules.
  - (vi) Projects: The Parishad shall obtain the prior consent of the State Government and Central Government before undertaking any new Project.

## **PROCEEDINGS OF THE PARISHAD**

14. The meetings of the Parishad shall be held at least twice a year at such time, date and place as may be determined by the President.
15. Except as otherwise provided in these rules, all meetings of the Parishad shall be called by the notice of not less than fifteen clear days under the signature of the State Project Director.
16. If the President is not present at the meeting of the Parishad, the Vice-President will chair the meeting.
17. One-third of the members of the parishad present in person shall form a quorum at every meeting of the parishad, provided that one quorum shall be necessary in respect of an adjourned meeting.
18. All disputed question at any meeting of the parishad shall be determined by vote and in case of equality of votes, the person chairing the meeting shall have a casting vote.

## **OFFICER & AUTHORITIES OF THE PARISHAD**

19. Officers : The officers of the parishad shall be the President, the Vice-President, the Chairman, the State Project Director, and such other person as may be designated as such by the executive committee.
20. The State Project Director of the Parishad shall be appointed by the State Government which shall prescribe his remuneration and other conditions of service.
21. Authorities : The following shall be the authorities of the Parishad

- (i) The President
- (ii) The Vice- President
- (iii) Chairman/Vice Chairman
- (iv) Executive Committee
- (v) State Project Director
- (vi) Such other authorities as may be constituted by the Executive Committee.

### EXECUTIVE COMMITTEE

22. The affairs of the Parishad shall be administered, subject to the Rule & Regulations and orders of the Parishad, by an Executive Committee, which shall consist of the following:

(i)	Chief Secretary, Government of Uttaranchal, Dehradun	Chairman Ex-officio
(ii)	Secretary, Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Vice-Chairman Ex-officio
(iii)	Secretary, or his nominee Department of Finance & Planning, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
(iv)	Secretary Department of Rural Development & Panchayati Raj, Government of Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
(v)	Addl. Secretary, Department of Education Government of Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
(vi)	Director of Education, Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
(vii)	Addl. Director of Education, Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
(viii)	Director/nominee of Deptt. of Women and Child Development, Uttaranchal, Dehradun	Member, Ex-officio
(ix)	Two Heads of District Task Force from amongst selected	Members

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

	districts by rotation to be nominated by the Chairman	
(x)	Two Heads of District Committees from amongst selected districts by rotation, to be nominated by the Chairman	Members
(xi)	Three nominees of the Central Government	Members
(xii)	Two Directors/Representatives of State level academic and technical resources support agencies to be nominated by the State Government	Members
(xiii)	Two educationists known for their experience and interest in education, one each to be nominated by the Central Government & State Government.	Members
(xiv)	Two women with experience and interest in women's development and education, one each to be nominated by the Central government and State Government	Members
(xv)	Two persons from voluntary agencies who have distinguished themselves for work among scheduled castes and scheduled tribes, one each to be nominated	Members
(xvi)	State Project Director of the Parishad	Member-Secretary Ex-officio

23. The term of the non official members nominated by the Central Government and the State Government shall be 2 years or the unexpired period there of in respect of a member nominated to fill in a vacancy.
24. Members of the Executive committee shall cease to be such member if :-
- A) They resign or are of unsound mind or are insolvent or are convicted of a criminal offence involving moral turpitude or
- B) They do not attend three consecutive meetings of the Executive Committee without proper leave of the Chairman.
25. A resignation of membership of the Executive Committee shall be tendered to the State Project Director and shall not take effect until it has been accepted on behalf of the Executive Committee by the chairman.
26. Vacancies: Any vacancy in the non official membership of the Executive Committee shall be filled up by nominations, and the person nominated in that vacancy shall hold office only for the remaining period of term of membership.

27. The Executive Committee shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by the reason of his office is not a member of the executive committee for the time being and notwithstanding any other vacancy in the committee whether on account of non nomination by the authority entitled to nominate or otherwise and no act or proceeding of the executive committee shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or defects in the nomination of any of its members.

## **PROCEEDINGS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE**

28. Every meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chairman and in his absence by the Vice Chairman and in the absence of the both by a member chosen by the members present at the meeting to chair for the occasion.
29. One third of the members of the Executive Committee present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Executive Committee, provided that no quorum shall be necessary in respect of an adjourned meeting.
30. Not less than 15 clear days notice of every meeting of the Executive Committee shall be given to each member of the Executive Committee provided that:
- A) The Chairman may call an emergency meeting at a notice of three days,
  - B) Non-receipt of notice of the meeting by any member shall not invalidate the proceedings of the meeting.
31. Every notice for a meeting of the Executive Committee shall state the date, time and place at which such meeting will be held and shall, except and otherwise provided in these rules, be under signatures of the member secretary.
32. The Executive Committee shall meet as often as necessary but least once in each quarter of the year.
33. Each member of the Executive Committee, including the Chairman shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be decided by the Executive Committee, the Chairman or in absence the Vice-Chairman or in the absence of both, the member presiding the meeting shall in addition, have a casting vote.
34. It shall be the responsibility of the Executive Committee to endeavor to achieve the objects of the Parishad and to discharge all its function, the Executive Committee shall exercise all the administrative, financial and academic function in this behalf including powers to create the posts of all description and make appointments thereon in accordance with regulations.
35. The Executive Committee shall have under its control the management of all the affairs and funds of the Parishad.

36. The Executive Committee shall have the powers and responsibilities in respect of the following:
- (i) To frame regulations with the approval of the State Government.
  - (ii) To frame by-laws for the conduct of activities of the Parishad in furthering its object.
37. The Executive Committee shall have the power to enter into contracts, agreements arrangement with other public or private organizations or individual for furtherance of its objects.
38. The Executive Committee shall have power for securing and accepting or providing endowments, grants-in-aid, donations, or gifts to or from Parishad on mutually agreed terms and conditions provided that condition of such Grant-In-Aid, donations, Gifts shall not be inconsistent or in conflict with the object of the Parishad or with the provisions of these rules.
39. The Executive Committee shall have the powers to take over and acquire by purchase, gift or otherwise from Government and other public bodies for private individuals, movable or immovable properties or other funds together with any attendant obligation and engagements not inconsistent with the objects of the Parishad and the provisions of these rules.
40. The Executive Committee shall have powers to undertake or give contract for construction of building required for use of the Parishad and to acquire stores and services required for the discharge of the functions of the Parishad.
41. **Property and assets :** The income and property of the Parishad however acquired, shall be applied towards promotion of the objects thereof as set forth in the Memorandum of Association, subject nevertheless, in respect of the expenditure of grants made by the government of Uttaranchal to such limitations as the government may, from time to time, impose. No portion of the income and property of the Parishad shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever by way of profit, to the person who at any time have been member of the Parishad or to any of them or to any person claiming through them provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other persons in return for any service rendered to the Parishad for traveling allowance, halting or other similar charges in accordance with the rules and regulations of the Parishad.
42. Subject to the provisions of Societies Registration Act (Act No. 21 of 1860), 1860 (hereinafter called the Act), the Executive Committee shall have the power to sell or lease any movable or immovable property of the Parishad provided however that no assets of the Parishad created out of Government Grants shall without the prior approval of government be disposed of, encumbered or utilized for purpose other than those for which the grant was sanctioned.
43. The Executive Committee shall have the powers to establish and spell out the member of standing/ad-hoc committees or task force group etc. for various areas of the education programme and decide in regard to their membership, power and functions.

44. The Executive Committee may by resolution appoint advisory board or other special committees for such purposes and with such powers as the executive committee may think fit & the Executive Committee may also dissolve any of the committee & advisory bodies, set up by it.
45. The Executive Committee may delegate, to Chairman, State Project Director or any of its members and/ or to a committee/ group or any other officer of the Parishad such administrative, financial and academic powers and impose such duties as it deems proper and also prescribe limitations within which the powers and duties are to be exercised or discharge.

## REGULATIONS

46. Subject to any specific directions of the Parishad and keeping in view overall advice of the State Government the Executive Committee shall have the powers to frame and amend Regulations, not inconsistent with these rules, for the administration and management of the affairs of the Parishad and without prejudice to the generality of this provision, such Regulations may provide for the following matters.
- (i) Service matters pertaining to officers and staff including creation of posts, qualifications, selection procedures, service conditions, pay and emoluments, discipline and control rules.
  - (ii) Important financial aspects including formula of budget, purchase procedure, delegation of financial powers, investments of funds, maintenance of accounts and audit, T.A. & D.A. Rules etc; and
  - (iii) Such other matters as may be necessary for the furtherance of the objects and proper administration of the affairs of the Parishad.

Provided that for the purpose of this rule, following guidelines would be kept in view while, creating new post and formulating the service and Financial Regulations.

- (a) Scales of the pay in respect of the posts to be created by the Executive Committee shall correspond to state government scales of pay.
- (b) Mode of recruitment in respect of the post to be created for the Parishad shall be either transferred on deputation or sort-term contract. For work related specific assignments, persons would be deployed on fixed emoluments with provision for revision each year, if considered appropriate.
- (c) In the management structure, staff which may develop permanent liability on the State Government shall not be appointed.
- (d) Till such time the Parishad formulates its own set of regulations, the decisions taken by the Executive Committee in all such matters will be carried out.

- (e) The principal of reservation as laid down by the State Government shall be followed.
- (f) Consideration of financial propriety and prudence shall be kept in view.

### **BY LAWS**

47. Subject to the specific directions of the Parishad and the provisions in these rule and regulations to be framed there under, the Executive Committee shall have powers to frame and amend by-laws for the conduct of the activities of the Parishad for achievement of it's objects and these by laws may, interlaid include matters relating to;
- (a) Conduct of business of Parishad, Executive Committee, and other committees and sub committees.
  - (b) Grant in aid to voluntary agencies.
  - (c) Involvement of individuals and contractual arrangements with them.
  - (d) School mapping and establishment of new schools, Non Formal Education Centers, college/ institutions and other education facilities.
  - (e) Facility and incentives to be provided to improve access and participation of children in education.
  - (f) All aspects of technical resource support.
  - (g) Such other things as may be necessary for implementation of the projects.

### **CHAIRMAN**

48. The Chief Secretary, Government of Uttaranchal shall be Ex -officio chairman of the Executive Committee. The Chairman includes the Vice-Chairman of the Executive Committee. The Chairman-
- (1) Shall ensure that the affairs of the Parishad are run efficiently and in accordance with the provisions of the project, the Memorandum of Association, Rules and Regulations and bylaws of the Parishad.
  - (2) Shall preside over the meetings of the Executive Committee.
  - (3) May himself call, or by a requisition in writing signed by him may require the member secretary to call a meeting of the Executive Committee at anytime.
  - (4) In case the vote for and against a particular issue are equal, may exercise his casting vote.
  - (5) Shall be sole and absolute authority to judge the validity of the vote cast by the members at all the meetings of the Executive Committee.



- (6) Shall be entitled to invite any other person to attend the meeting of the Executive Committee provided that such persons shall have no right of voting, and
- (7) May direct the member secretary to call a special meeting of the Executive Committee at a short notice, in case of emergency.

## **POWER AND FUNCTIONS OF THE STATE PROJECT DIRECTOR**

49. The Project Director shall be the principal executive officer of the Parishad and shall be responsible for the proper administration of the affairs and funds of the Parishad and implementations of various activities of the educational project in a mission mode under the directions and guidance of the chairman of the Executive Committee. For the effective discharge of his functions shall have powers to :
- (a) Constitute steering group for each of the Programme components and functional areas.
  - (b) Constitute a task force, comprising head of the steering groups which would function as a cohesive team further achievement of the object of the educational project.
  - (c) Prescribe the duties of all the officers and staff of the parishad.
  - (d) Exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary.
  - (e) Coordinate and exercise general supervision over the activities of the Parishad including it's branches and units.
  - (f) Conduct meetings of the Parishad and the Executive Committee and keep a record of proceedings of these meetings in accordance with these rules, and
  - (g) Discharge such other functions as may be assigned to the Executive Committee in furtherance of the objects of the Parishad.

## **DISTRICT MANAGEMENT STRUCTURE**

50. The District Education Project Committee at the district level will review the progress of the project and widen involvement of participating agencies. It will be headed by the District Magistrate concerned and shall have such members as shall be determined by the executive committee upon the nomination of the District Magistrate.
51. The District Task Force will be the executive body at the district level to whom well defined powers will be delegated. The Chairman of the District Task Force will be decided by the Executive Committee and its membership will include district level official and representatives of interested agencies. The total members the task force shall not exceed 15.

## FUNDS OF THE PARISHAD

52. The funds of the Parishad shall consist of the following:
- (a) Grant-in-aid made by the Central Government and the Government for furtherance of the objects of the Parishad.
  - (b) Contribution from other sources.
  - (c) Income from the assets of the Parishad.
  - (d) Receipts of the Parishad from other sources, and
  - (e) Grants, Donations, Assistance of any kind from foreign governments and other external agencies with prior approval the Central Government.
53. The Bankers of the Parishad shall be decided by the Executive Committee. All funds shall be paid into the Parishad account shall not be withdrawn except through a cheque signed by officers as may be duly empowered in this behalf by the Executive Committee.
54. (i) The Parishad shall maintain proper account and other relevant records and prepare annual accounts comprising the receipt and payments account. Statement of liabilities in such forms as may be prescribed by the Registrar of Societies of the State Government keeping with the rules under the Societies Registration act 1860.
- (ii) The accounts of the Parishad shall be audited annually by an independent chartered accountant and in accordance with the provisions of the Societies Registration Act 1860.
  - (iii) The audited accounts shall be communicated to the Parishad which shall submit a copy of the audit report along with the observations to the State Government within a fortnight from the date of receipt there of by it.
  - (iv) The accounts of the Parishad shall also be subject to the provisions of the Comptroller of the Auditor General (duties, power and conditions of service) Act 1971, as amended from time to time.

## ANNUAL REPORT

55. The Annual Report on the working of the Parishad and the work undertaken by it during the year together with the balance sheet and audited accounts shall be prepared by the Executive Committee. A draft of the annual report shall be placed before the Parishad for consideration, which after it's approval shall submit to the State Government. The State Government would, with comments, if any, forward the annual report along with the audited accounts of the Parishad, and audit report to the Central Government for acceptance.

## AMENDMENTS

56. With the prior approval of the State Government and the Central Government, the Parishad may alter, expand or abridge the purpose for which it is established, or amalgamate the Parishad either wholly or partially with any other society in accordance with the provisions of the Societies Registration Act 1860, as applicable to the State of Uttaranchal.
57. As and when there is any change in the nomenclature of Ministries, Departments, or Institution(s) and designation(s) mentioned in the rules, such change shall automatically stand incorporated in these rules.
58. If the Parishad needs to be dissolved, it shall be dissolved as per the provisions laid down u/s 13 & 14 of the Societies Registration Act 1860, as applicable to the State of Uttaranchal,
59. If, on the winding up or dissolution of the Parishad, there shall remain after the satisfaction of all its debt and liabilities, any assets and property whatsoever, the same shall not be paid to, or distributed amongst the members of the Parishad or anyone of them but shall be transferred by the Parishad to the State Government, which will decide about its utilization in accordance with the provisions of the Societies Registration Act 1860.
60. Common Seal: The Parishad shall have a common seal as the Executive Committee may approve.
61. Government's Powers: The State Government and the Central Government may jointly appoint one or more persons to review the work and progress of the Parishad, and to hold inquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the Government may stipulate; and upon receipt of any such report, the State Government may in consultation with the Central Government issue such directions as it may consider necessary, in respect of any of the members dealt within the report, and the Parishad shall be bound to comply with such directions, In addition, the State Government in consultation with the Central Government may at any time, issue directives on matters of policy to the Parishad and the latter shall promptly comply with such directives. Where there is any divergence of view of the State Government and the Central Government, the views of the Central Government would prevail.

## MISCELLANEOUS

62. Once in every year, a list of members of the Executive Committee shall be filed with the Registrar of Societies as required U/S 4 of the Societies Registration Act, 1860.

We, the following members of the Executive Committee, certify that the above is a correct copy of the rules of the society:-

Sl.	Name and Address	Signature
1.	N.Ravi Shankar, Secretary, Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Sd/-
2.	Dr. Dilbag Singh, Addl. Secretary. Department of Education, Government of Uttaranchal, Dehradun	Sd/-
3.	Nand Nandan Prasad Pandey, Addl. Director Education, Uttaranchal, Dehradun.	Sd/-